# भारतीय जनता पार्टी

*(केन्द्रीय कार्यालय)*
11, अशोक रोड नई दिल्ली – 110001

## भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह द्वारा 9 जून, 2008 को मुम्बई में जारी प्रेस वक्तव्य

संप्रग सरकार ने सत्ता में रहते हुए चार वर्ष पूरे कर लिए है और अब उसने चुनावी वर्ष में प्रवेश कर लिया है। विगत चार वर्षों से यह सरकार देश क आन्तरिक तथा बाह्‌य दोनों प्रकार के मामलों की बद–इन्तजामी कर रही है, जिससे भारत घरेलू मुहाने पर अव्यवस्था का शिकार हो गया है और विदेशी मामलों के बारे में अलग–थलग पड़ गया है।

### संप्रग की देन है भारी आघात और उच्च्व मुद्रास्फीति

संप्रग शासन के दौरान आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों ने समाज के हर तबके की जिन्दगी मुश्किल कर दी है। गत सप्ताह 8.24 प्रतिशत को छूती हुई मुद्रास्फीति की दर इस बात का स्पष्ट संकेत है कि देश की अर्थव्यवस्था का कुप्रबन्धन नई ऊंचाई पर जा पहुंचा है।

इस समय देश का आर्थिक परिदृश्य अति विकराल दिखाई पड़ता है। हाल ही में संप्रग सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में रिकार्ड नौवीं बार वृद्धि की है, जो देश को द्वि–अंकीय मुद्रास्फीति के युग में धकेल देगी।

संप्रग सरकार अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए दीर्घकालीन नीतियां बनाने में विफल रही है। भारत संसार में पेट्रोलियम उत्पादों के सर्वाधिक आयातक देशों में से एक है। हमको राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा के मुद्‌दे पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए था। किन्तु सत्ता में चार वर्ष पूरे करने के पश्चात् भी संप्रग सरकार को अपनी नई पेट्रोलियम नीति घोषित करनी बाकी है।

जबसे राजग सरकार ने सत्ता छोड़ी है तब से पेट्रोल तथा डीज़ल के मूल्यों में क्रमशः 60 से 52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि इस सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के बढ़ते हुए मूल्यों की भीषण स्थिति का सामना करने के लिए कोई कंटिनजैंसी प्लान तैयार किया गया होता तो उपभोक्ताओं को इस भारी मूल्यवृद्धि से बचाया जा सकता था।

वर्ष 2007–08 में पेट्रोलियम पदार्थों पर कुल राजस्व–प्राप्ति 1,64,000 करोड़ रूपए थी, जिसमें सरकार को आधे से अधिक की प्राप्ति हुई थी। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ऑयल मार्किटिंग कम्पनियों पर CESS लगाकर लगभग 7,500 करोड़ की कमाई करती है। इस पर भी सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य बढ़ाकर लोगों को भारी बोझ के नीचे दबा दिया है।

संप्रग सराकर ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे राजस्व में अपने उस अल्प शेयर में कटौती करें, जो वे पेट्रोल की बिक्री पर कर लगाकर प्राप्त करती हैं। केन्द्र सरकार को तेल की बिक्री के माध्यम से भारी राजस्व प्राप्त होता है, किन्तु केन्द्र सरकार ने अपनी ड्‌यूटियों में समुचित कमी नहीं की है।

केन्द्र का राज्यों को पेट्रोलियम की बिक्री पर करों में कटौती करने के निर्देश से कई राज्यों के राजकोषों पर कुप्रभाव पड़ने की संभावना है। अतः पेट्रोलियम उत्पादों पर विद्यमान ड्‌यूटी–स्ट्रक्चर को केन्द्र

सरकार द्वारा युक्ति संगत बनाया जाना चाहिए तथा राज्यों की उनकी राजस्व हानि के लिए समुचित रूप में प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। **मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार पेट्रोल उत्पादों पर ड्यूटियों तथा करों को युक्तिसंगत बनाने के बारे में देश के सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाए।**

**इस देश के लोग कांग्रेस पार्टी से एक प्रश्न पूछना चाहते है कि उसका शासनकाल ऊंची मुद्रास्फीति तथा ऊंचे मूल्यों का पर्यायवाचक क्यों बन गया है?**

मुझे उन तरीकों पर हैरानी हो रही है, जिनके सहारे श्री पी.चिदम्बरम तथा डॉ. मॉन्टेक सिंह अहलुवालिया जैसे अर्थशास्त्र के पंडित मुद्रास्फीति को उच्च विकास दर के साथ न्यायोचित ठहरा रहे हैं। डॉ. अहलुवालिया ने तो यहां तक टिप्पणी कर डाली है "उच्च विकास दर तथा न्यून मुद्रास्फीति साथ–साथ नहीं चल सकते है।"

भारत श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अर्थव्यवस्था सम्बन्धी पटुता का साक्षी रहा है, जिन्होंने देश में न केवल विकास की गंगा बहाई, बल्कि मुद्रास्फीति को भी सफलतापूर्वक सतत नियंत्रण में रखा। यदि राजग सराकर ऐसा कर सकती थी तो संप्रग सरकार ने ऐसा प्रदर्शन क्यों नहीं दोहराया ?

**ऐसा प्रतीत होता है कि वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम पर न्यू एज मार्किटिंग का गहरा प्रभाव है, जिससे वे उत्पादों की गुणवत्ता से उनके प्रोमोशन तथा पैकेजिंग को अधिक महत्व देते हैं। श्री चिदम्बरम द्वारा इस वर्ष बनाए गए वार्षिक बजट का आकर्षक पैकेजिंग तथा आक्रामक प्रोमोशन पर अधिक बल था। किन्तु जैसा कि हम सभी जानते है कि जिस उत्पाद के बारे में गुणवत्ता से समझौता किया जाता है वह विफल रहता है। इस वर्ष के वार्षिक बजट की नीतियां और कार्यक्रम भी कोई प्रभाव नहीं डाल पाए हैं।**

संप्रग सरकार ने भारत के खाते में राजग शासन के दौरान दर्ज सभी आर्थिक लाभों को उलट डाला है और अब हम ऐसे बिन्दु पर जा पहुंचे है जहां पर आर्थिक मंदी की आशंका है।

## आत्मसंतुष्ट यूपीए चीन के सामरिक विस्तार में सहायक

विगत चार वर्षों के दौरान भारत ने विदेशी मामलों के मोर्चे पर राजग द्वारा प्राप्त राजनयिक बढ़त को गंवा दिया है। जिस ढंग से संप्रग सरकार चीन जैसे हमारे पड़ौसी देशों को तुष्ट करने पर लगी है उससे हमारे सामरिक हित जोखिम में पड़ गए है।

**सिक्किम के "फिंगर प्वाइंट" क्षेत्र पर चीन का हाल का दावा भारत के साथ उसके ढीठ व्यवहार का एक और उदाहरण है। जब राजग सरकार सत्तारूढ़ थी तब चीन ने सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग मान लिया था।** भारतीय भू–क्षेत्रों पर चीन के लगातार दावों ने संप्रग की राजनयिक पटुता की पोल खोल कर रख दी है। इन दावों के ब्यौरों को छिपा कर सरकार लोगों को अंधकार में रखने का प्रयास कर रही है।

**भाजपा की मांग है कि सरकार सिक्किम में "फिंगर प्वाइंट" पर चीन के दावों के इन ब्यौरों को स्पष्ट करे। लद्दाख तथा पूर्वोत्तर में भारतीय भू–भाग पर चीनी सैनिकों द्वारा किए जा रहे लगातार अतिक्रमण के प्रति दब्बू प्रतिक्रिया ने भारत को कमजोर निशाना बना डाला है।**

संप्रग सरकार के आत्मतोस से शह पाकर चीन एक ओर कई महत्वपूर्ण राजनयिक मुद्दों पर भारत को झिड़की दे रहा है वहीं दूसरी ओर वह इस क्षेत्र में अपनी सामरिक स्थिति का विस्तार करने में लगा हुआ है।

चीन ने हाल ही में एक न्यूक्लियर सबमेराइन बेस स्थापित किया है, जो मलक्का स्ट्रेट से मुश्किल से 1200 नौटिकाल मील दूर है। उसने साउथ चाइना समुद्र में हैनान द्वीप पर सान्या में अपने जिन क्लास अन्डरग्राउंड न्यूक्लियर सबमेराइन तैनात कर दिए है। इसने इस क्षेत्र में चीन की उपस्थिति और अधिक दृढ़ कर दी है। पाकिस्तान में ग्वादर में सी पोर्ट का निर्माण, म्यंमार में कोको द्वीप समूह में रेडार का संस्थापन और श्रीलंका में हुम्बान टोटा में एयरपोर्ट का निर्माण करके चीन भारत को चारों ओर से घेर रहा है।

**संप्रग सरकार को चीन की आक्रामक नीतियों और इसके सामरिक विस्तार की ओर से आँखें नहीं मूंदनी चाहिए। चीन के विस्तारवादी मनसूबे की अनदेखी करके हम अपने सामरिक हितों को सुरक्षित रखने में समर्थ नहीं हो पाएंगे।**

## आतंकवाद का बढ़ता खतरा

लगभग दो वर्ष पहले 11 जुलाई, 2006 को लोकल ट्रेनों में लगातार धमाकों से बम्बई शहर दहल उठा था। तब से हमने देश के विभिन्न हिस्सों में अनेक लगातार धमाके हुए देखें है। किंतु संप्रग सरकार की आतंकवाद के प्रति प्रतिक्रिया केजुअल और कम्प्लेसेंट रही है। जयपुर में हुए हाल के धमाकों ने स्पष्ट कर दिया है कि संप्रग शासन के अधीन भारत में आतंकवादी फलफूल रहे हैं और हर गुजरते हुए दिन वे देश में मनमानी जगहों पर हमला करने में अधिक साहस दिखा रहे हैं।

सत्तारूढ़ सरकार बढ़ते आतंकवाद के मूल कारण की पहचान करने से मुंह छिपा रही है। जयपुर सीरियल धमाकों के बाद प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा था कि ये धमाके जयपुर के लोगों के विरूद्ध नहीं बल्कि भारत–पाक के द्विपक्षीय संबंधों को बिगाड़ने के उद्‌देश्य से किए गए थे। यह ठीक ऐसा ही बयान था जैसा प्रधानमंत्री ने मुंबई धमाकों के कुछ दिन बाद हवाना में दिया था कि पाकिस्तान भी भारत की ही तरह आतंकवाद का शिकार है।

प्रधानमंत्री के बयान को देश के लोगों द्वारा वास्तविक मुद्‌दों से ध्यान हटाने के एक प्रयास के रूप में देखा गया था। संप्रग सरकार के पास आतंकवाद के बढ़ते खतरे से जूझने का न तो जीवट है और न ही इच्छा।

संसारभर में भारत पर आतंकवाद ने सबसे अधिक कड़ा प्रहार किया है। **"ग्लोबल टैरेरिज़्म इन 2007" के बारे में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की हाल की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया है, "भारत संसार का सर्वाधिक आतंकवाद प्रभावित देश बना हुआ है, इसके कारण इस वर्ष 2,300 लोगों ने जान गंवाई। 2007 में विश्वभर में आतंकवादियों द्वारा मारे गए कुल 22,685 लोगों की यह लगभग 10 प्रतिशत संख्या है।"**

रिपोर्ट में आगे लिखा गया है, "भारत सरकार के आतंकवाद विरोधी प्रयासों में आउटडेटिड और ओवरबर्डन्ड लॉ एन्फोर्समेंट एंड लीगल सिस्टम के कारण बाधा पहुंचती है। भारत की न्यायालय प्रणाली धीमी, श्रमसाध्य और भ्रष्टाचारभरी होती है। आतंकवाद से संबंधित मुकद्‌दमों में निर्णय होने में वर्षों लग जाते है।" फिर भी संप्रग सरकार देश में आतंकवाद विरोधी कानून न बनाने पर अड़ी हुई है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने भी कठोर आतंकवाद विरोधी कानूनों की आवश्यकता पर बल दिया है।

भाजपा देश में आन्तरिक सुरक्षा के बिगड़ते हुए परिदृश्य और बढ़ते हुए आतंकवादी हमलों के बारे में बेहद चिंतित है। **मेरी सरकार से मांग है कि वह आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए एक विशद समन्वित योजना तैयार करे। भाजपा देश को आश्वस्त करती है कि वह इस मुद्‌दे पर सरकार को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।**